vinetur

व्यापार समझौते के तहत न्यूज़ीलैंड की वाइन पर भारत का शुल्क 150% से घटकर 25% तक होगा

न्यूज़ीलैंड के उच्चायुक्त के मुताबिक, वाइन शुल्क में कटौती दस वर्षों में लागू होगी और भारतीय बाज़ार की एक बड़ी बाधा कम करेगी

गुरुवार, 19 नवंबर 2026



भारत-न्यूज़ीलैंड मुक्त व्यापार समझौते के तहत भारत में न्यूज़ीलैंड से आयात होने वाली वाइन पर शुल्क 10 वर्षों में 150% से घटाकर 25% या 50% किया जाएगा। भारत में न्यूज़ीलैंड के उच्चायुक्त Patrick John Rata ने बुधवार, 18 नवंबर को मुंबई में यह बात कही।

Rata ने ProWine Mumbai 2026 से इतर यह टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि 20 न्यूज़ीलैंड कंपनियां कारोबारी अवसरों का आकलन करने और भारतीय आयातकों, खुदरा विक्रेताओं, थोक विक्रेताओं तथा आतिथ्य उद्योग से संपर्क बनाने के लिए भारत आई हैं। उनके मुताबिक, व्यापार समझौते से शुल्क में रियायतें और व्यापक कारोबारी अवसर पैदा होंगे, जिससे भारतीय बाज़ार न्यूज़ीलैंड की कंपनियों के लिए अधिक आकर्षक बनेगा।

Rata के अनुसार, इनमें से कई कंपनियों की सबसे बड़ी तात्कालिक दिलचस्पी वाइन में है। उन्होंने कहा कि न्यूज़ीलैंड से भारत आने वाली वाइन पर मौजूदा 150% शुल्क को दस वर्षों में धीरे-धीरे घटाकर 25% या 50% किया जाएगा। उन्होंने यह नहीं बताया कि किन उत्पादों पर अंतिम शुल्क की कौन-सी दर लागू होगी या 10 वर्षों में कटौती किस तरह चरणबद्ध ढंग से की जाएगी।

Rata द्वारा बताई गई शर्तों पर इस बदलाव को लागू किए जाने से न्यूज़ीलैंड के वाइन उत्पादकों के लिए भारतीय बाज़ार तक पहुंच में बड़ा बदलाव आ सकता है। भारत का मौजूदा आयात शुल्क विदेशी वाइन के लिए लागत की एक बड़ी बाधा रहा है, और कम शुल्क से न्यूज़ीलैंड के ब्रांडों को वितरण तथा मूल्य निर्धारण के विकल्प बढ़ाने की गुंजाइश मिल सकती है। पेय उद्योग के लिए इससे भारत में न्यूज़ीलैंड की वाइन की पहुंच बेहतर हो सकती है और रेस्तरां, होटलों तथा खुदरा माध्यमों को आपूर्ति करने वाले विदेशी आपूर्तिकर्ताओं, आयातकों और स्थानीय वितरकों के बीच प्रतिस्पर्धा का स्वरूप भी बदल सकता है।

Rata ने कहा कि यह समझौता वाइन तक सीमित नहीं है और इससे न्यूज़ीलैंड के भेड़ के मांस, कीवी फल तथा शहद जैसे उत्पादों के निर्यात के अवसर भी बनेंगे। साथ ही, उन्होंने इस समझौते को संतुलित और महत्वाकांक्षी नतीजा बताया, जिससे न्यूज़ीलैंड को निर्यात करने वाले भारतीय कारोबारियों को भी लाभ होगा।

उनकी टिप्पणियों से पता चलता है कि न्यूज़ीलैंड के अधिकारी और कंपनियां ऐसे बाज़ार में जल्द अपनी जगह बनाने की कोशिश कर रहे हैं, जहां उनके विचार में विकास की गुंजाइश है। Rata ने कहा कि भारत में शराब की कुल खपत में वाइन की हिस्सेदारी अभी बहुत कम है। हालांकि, उन्होंने संकेत दिया कि जैसे-जैसे उपभोक्ता इस श्रेणी से अधिक परिचित होंगे और भारत में वाइन की मांग लंबे समय में बढ़ेगी, न्यूज़ीलैंड भी इस वृद्धि का हिस्सा बनना चाहता है।

विकास की यही संभावना ProWine Mumbai में न्यूज़ीलैंड की बड़ी मौजूदगी को समझने में मदद करती है। Rata ने कहा कि इसमें शामिल कंपनियां केवल अपने उत्पाद पेश नहीं कर रही थीं, बल्कि यह भी समझने की कोशिश कर रही थीं कि भारतीय बाज़ार कैसे काम करता है—व्यापारिक साझेदारों से कैसे जुड़ें और वितरण शृंखला के अलग-अलग चरणों में खरीदारों तक अपनी वाइन कैसे पहुंचाएं।

इन टिप्पणियों से यह भी संकेत मिलता है कि व्यापार समझौते का असर सीधे निर्यात की मात्रा से आगे तक हो सकता है। कम शुल्क से भारत में न्यूज़ीलैंड की वाइनरी ब्रांड निर्माण, विपणन और अपने उत्पादों की श्रृंखला का विस्तार करने के लिए प्रोत्साहित हो सकती हैं। खास तौर पर उन श्रेणियों में, जहां आयातित वाइन को दुकानों की शेल्फ़ पर जगह पाने और रेस्तरां व होटल की वाइन सूची में शामिल होने के लिए प्रतिस्पर्धा करनी पड़ती है। हालांकि, Rata द्वारा बताई गई 10 साल की संक्रमण अवधि और व्यापक शराब क्षेत्र की तुलना में भारत के वाइन बाज़ार का आकार अभी सीमित होने के कारण ऐसा कोई भी बदलाव धीरे-धीरे होगा।

Rata ने समझौते को एकतरफा लाभ के बजाय कारोबारी अवसर के रूप में पेश किया। उन्होंने न्यूज़ीलैंड के कारोबारियों के लिए बाधाएं घटने से बनने वाले अवसरों पर जोर दिया, लेकिन यह भी कहा कि इसी समझौते के तहत भारतीय निर्यातकों के लिए भी अच्छे अवसर होंगे। इससे उस व्यापार समझौते का द्विपक्षीय स्वरूप रेखांकित होता है, जिसके संपन्न होने की बात उन्होंने कही।